>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2009 (Bill under consideration).

MADAM SPEAKER: Now we will take up item no. 11.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, I beg to move:*

"That the Bill to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."

Madam Speaker, with a view to increase access and improve quality of higher education in the country and also to remove regional imbalances in the higher education sector, the Central Universities Ordinance, 2009 was promulgated way back on 15th of January, 2009. Under this Ordinance, we were able to convert three State Universities in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttarakhand into Central Universities and we decided to establish Central Universities in 12 States so that there would be no State in India which would not have a Central University and one of the 12 States in which we decided to set up a Central University was Jammu and Kashmir.

Now, the parameter for setting up a Central University is that the State Government has to provide land, free of cost, to the extent of about 500 acres and then we set up Site Selection Committee. When the State Government tells us as to which are the sites that are possible for the purposes of setting up these universities, we would then, after the stipulation of the exact sites, send the Site Selection Team to the sites and ultimately the final selection is to be made by the Central Government on the basis of the recommendation of the Site Selection Committee with respect to the exact location of the university. After the location is finalized, then we issue a notification under Section 3 (v) of the Central Universities Act, 2009. So, this was the procedure that we have set up.

Now, the Government of Jammu and Kashmir had informed way back in July, 2008 that a Committee constituted by the State Government had identified three sites in and around Jammu for the purpose of setting up of a Central University and efforts were being made to actually find out more sites other than the three that they had suggested. But, unfortunately, they never indicated the exact sites and because they did not indicate the exact sites, we could not send the Site Selection Team.

In the mean time, Vice-Chancellors were appointed by the previous UPA Government to all the 15 Central Universities by the then hon. Minister of Human Resource Development. So, wherever the sites were selected, the Vice-Chancellors set up universities temporarily in those sites, but wherever the sites were not selected, they went to the State Capital and set up an office and decided to run the university temporarily till a site was selected.

So, the Vice-Chancellor of the Jammu and Kashmir Central University set up the office in Srinagar. When this happened, there was a furore because the people of Jammu thought that they were being deprived of a Central University as the State Government had earlier written to us saying that they had identified three sites in Jammu. Therefore, this created a lot of misgivings and, as you know – and we have seen it in the past – there were certain vested interests which tried to take advantage of the situation. In the mean time, the Vice-Chancellor had started activities in Srinagar and the people of Srinagar thought that they would be deprived because they assumed that since the Vice-Chancellor started activities there and if it is moved to Jammu now, they will not get the university. So, the people of Jammu thought that they are being deprived of a Central University and the people of Srinagar thought that the Central University was being taken away from Srinagar. In this situation, there was a lot of confusion and there was an upsurge of sentiments.

So we thought that it would be best in this context to remove the regional imbalances and to avoid a very unseemly situation that could have arisen, we decided that it would be expedient, in the case of Jammu and Kashmir only – because of the peculiar circumstances that have arisen here – to set up two separate Universities, one for the Jammu region and one for the Kashmir Valley and to restore regional harmony in the State. So we have decided to rename the original Central University, and we renamed it Central University of Jammu and Kashmir, and then we have a Central University of Kashmir and a new Central University of Jammu. So now we have a Central University of Kashmir and a Central University of Jammu, and appropriate amendments had to be made in the Central Universities Act.

But, since, this is an ongoing process and since we want to be ready for the next academic year, we decided to issue an Ordinance in the meantime. So, in those circumstances, the Central Universities (Amendment) Ordinance of 2009 was therefore promulgated on the 20th of October, 2009 to amend the Central Universities Act. By way of these amendments, the Central University of Jammu and Kashmir will be renamed as the Central University of Kashmir with territorial

jurisdiction limited to the Kashmir Division. And a new University bearing the name of Central University of Jammu will have territorial jurisdiction extending to the Jammu Division, which has been established.

It is in these circumstances that we are moving the Bill. The financial requirement of the new Central University of Jammu during the Eleventh Plan period is estimated to be Rs. 240 crore: Rs. 160 crore non-recurring and Rs. 78 crore recurring. This expenditure will be met by the Central Government through the University Grants Commission. The Bill seeks to replace the Central Universities (Amendment) Ordinance, 2009.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की बात रखी है। हिन्दुस्तान में शिक्षा का स्तर किस तरह से ऊपर आए, उसके लिए समय-समय पर विभिन्न प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें प्रयास करती रही हैं। जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी की बात मंत्री जी ने यहां रखी है, लगभग 12 प्रदेशों में 12 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई। हर प्रदेश के लिए एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई। पिछले लगभग कितने वर्ष में कितने राज्यों में अब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की क्लासेज शुरु की गई, अगर उसकी जानकारी सदन को मिले तो अच्छा होगा। क्या कारण है कि आज जम्मू-कश्मीर में एक की बजाए दो विश्वविद्यालय देने की बात कही गई? क्या केवल वहां पर क्षेत्रवाद को बढ़ाने की बात नहीं कही गई? क्या हिमाचल प्रदेश जो उसी तरह से एक पर्वतीय राज्य है जिसका एक भाग चीन के बॉर्डर के साथ लगता है तो दूसरा भाग चम्बा में पाकिस्तान के साथ लगता है। अगर जनसंख्या को देखा जाए तब भी हमारा अधिकार भी उसी तरह से दो विश्वविद्यालयों का बनता है। क्या उत्तर प्रदेश और बड़े राज्य भी कल को मांग करेंगे तो क्या वहां पर ज्यादा केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात करी जाएगी? क्या कल को लेह-लद्दाख वाले भी कहेंगे कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए तो क्या केन्द्र सरकार एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कहेगी?

जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, आज हिन्दुस्तान की जरूरत है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय खुलें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जहां पर हजारों-लाखों विद्यार्थी देश के अंदर और देश के बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, आज यह जरुरी हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा के संस्थान हिन्दुस्तान में खुलें। लेकिन वहीं पर मेरा यह मानना भी है कि जहां पर कई राज्य ऐसे हैं जिसमें मैं विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश की बात भी करूंगा, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को भी केन्द्र सरकार की तरफ से दिया गया।

श्री पी. चिदंबरम जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहॉफ पर शिमला में आकर घोषणा की कि एक आईआईटी और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में बनेगा। यह 2 अक्टूबर, 2007 की बात है। उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि आईआईटी जिला मंडी में और केंद्रीय विश्वविद्यालय जिला कांगड़ा में खोला जाएगा। जब केंद्रीय टीम निरीक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश आई तब उन्हें जिला कांगड़ा में चार स्थान पालनपुर, धर्मशाला, कांगड़ा और साथ लगते क्षेत्र दिखाए गए। सरकार ने देहरा में 695 एकड़ जमीन देने की बात केंद्र सरकार के सामने रखी। टीम मंडी में आईआईटी का दौरा करने के बाद फिर वापिस कांगड़ा में आई और अन्य स्थान दिखाने की बात कही। इसके अलावा लगभग 20 और 30 एकड़ के अन्य स्थान दिखाए गए। जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हुए दो यूनिवर्सिटी दी गई, हम इसका स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। हमने लगभग एक वर्ष से केंद्र सरकार से बार-बार मांग की। हमारे मुख्यमंत्री ने निवेदन किया कि जब पूरे कांगड़ा जिले में एक स्थान देहरा में 695 एकड़ जमीन उपलब्ध है, प्रदेश सरकार इसे केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं यूनिवर्सिटी की क्लासेज शुरू करने की तैयारी कर रही है? हमने इससे केवल 15 किलोमीटर दूर ज्वाला जी स्थान पर कॉलेज की बिल्डिंग देने की बात कही और कहा कि यहां आप पहले वर्ष की क्लासेज, पहला सेशन शुरू करें लेकिन पिछले वर्ष वह भी शुरू नहीं किया गया। आज केवल एक जोधपुर की सांसद लिखकर देती हैं कि धर्मशाला में 400 एकड़ जमीन उपलब्ध है लेकिन एक बार फिर से उस केस को पेंडिंग कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है? क्या जानबूझकर हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए डिले किया जा रहा है? इसके लिए 500 एकड़ भूमि चाहिए लेकिन हम तो 695 एकड़ भूमि दे रहे हैं फिर क्यों नहीं खोला जा रहा है? जिस भूमि की बात धर्मशाला में कही गई, वहां हजारों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं, रिजर्वड फारेस्ट है। देहरा की भूमि, जिसकी बात मैं कह रहा हूं, यह अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, यहां विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जिन क्षेत्रों में लोग हथियार उठाते हैं, वहां दो यूनिवर्सिटी दी जाती हैं। जहां दंगे-फसाद और धरने दिए जाते हैं वहां दो यूनिवर्सिटी दे दी जाती हैं। लेकिन जो शांतिप्रिय प्रदेश है, जहां हजारों नौजवान इस देश की सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं, वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने में डिले किया जा रहा है।

महोदया, केवल इतना ही नहीं, अगर पूरे देश को हायर एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए कि किस प्रदेश में एनरोलमेंट सबसे ज्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश में 22 प्रतिशत है। क्या इस आधार पर हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बल्कि दो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुलने चाहिए? आज क्या केवल क्षेत्रवाद और विपक्ष सरकार को देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने में विलंब नहीं किया जा रहा है? पिछले एक वर्ष में कई चिट्ठियां लिखी गई और कई बार मंत्री जी से मिला गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है? कौन से राज्य हैं जहां अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई? अगर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य तीन विश्वविद्यालय की मांग करता है तो क्या केंद्र सरकार तीन विश्वविद्यालय देगी? राजस्थान के लिए कितने विश्वविद्यालय देने की बात कही गई है? आज हमें तय करना है कि किस तरह से कितने विश्वविद्यालय कहां दिए जाएंगे? शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। कल हमने टीवी में देखा कि कैट के ऑनलाइन एग्जाम में हजारों लाखों की संख्या में नौजवानों को परीक्षा देने में दिक्कत हुई, परीक्षा रद्द की गई। निश्चित तौर पर समय के साथ शिक्षा के स्तर में बढावा होना चाहिए और लाखों की तादाद में लोगों को शिक्षा भी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन आज जो केंद्र सरकार कर रही है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न लग रहा है।

जम्मू-कश्मीर राज्य में दो विश्वविद्यालय जबकि हमारे राज्य में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। पिछले एक वÂान में जमीन उपलब्ध कराने के बावजूद भी वहां विश्वविद्यालय नहीं खोल पाये हैं। मैंने अपनी ओर से बार बार इस मांग को उठाया है और आज भी उठाना चाहूंगा। केवल इतना ही नहीं...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Thakur, you may continue your speech later on.

The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.